हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 211 देहरादून, शनिवार, 11 फरवरी, 2023 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

चिकित्सक ईमानदारी से निभाएं फ़र्ज़ , सरकार जनता के लिए समर्पित - डॉ आर राजेश कुमार 3

देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन

ग्रामीण विकास को इससे मिलेंगे नये आयाम : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 10 फरवरी,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संपूर्ण विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अविष्कारों और अनुसंधानों के इस युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकि विकास की चेतना ने सभी के जीवन को प्रभावित किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई ने जय जवान, जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान जोड़ा वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़कर एक नया आयाम दिया।

यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस -2023 के अन्तर्गत 'प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस' का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का यह देश का पहला आयोजन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के समेकित विकास को गति प्रदान करने में यह आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हाइड्रोपोनिक यूनिट, क्यू आर कोड आधारित जैव विविधता पार्क एवं प्राईड ऑफ उत्तराखण्ड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरोधा सम्मान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है। प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग से राज्य में जैविक कृषि को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से ही किसी राज्य और देश के विकास का प्रारूप तैयार होता है। इस विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य हमारे गांवो का समुचित विकास करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिये गौरव का विषय है कि नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में यूकास्ट उत्तराखण्ड को बेस्ट पैवेलियन का अवार्ड मिला। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह आयोजन इस संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस ग्राम्य विकास की दिशा में एक अनूठा प्रयोग है। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, कृषि, ग्रामीण पर्यटन और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस 2025 तक सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए रौडमैप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राम्य विकास एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। पिछले दो सालों में राज्य में जैविक खेती के क्षेत्र में काफी कार्य हुए है। राज्य में 34 प्रतिशत जैविक उत्पादन हुआ है, जिसे 2025 तक 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि के साथ ही हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। एप्पल एवं कीवी मिशन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से मिलेट को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

पद्मभूषण, पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान और कृषि से जुड़े लोग एक मंच पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो यह विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, इसके आने वाले समय में काफी सार्थक परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का समन्वय बहुत जरूरी है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा। यह पलायन को रोकने में भी काफी कारगर होगा। लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना होगा। इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, सचिव शैलेश बगोली, महानिदेशक यूकास्ट प्रो. दुर्गेश पंत, वैज्ञानिक डॉ. डी.के. असवाल, आयोजक सचिव डॉ. अपर्णा शर्मा, विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं विभिन्न राज्यों से आये वैज्ञानिक उपस्थित थे।

नकल विरोधी कानून से आच्छादित होंगी आगामी सभी परीक्षाएं : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

- हम किसी भी कीमत पर चाहते हैं छात्रों का हित
- कानून के तहत किए गए हैं जुर्माना और सजा का कठोर प्रावधान

देहरादून, 10 फरवरी , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। इसीलिए जिन भी परिक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निशुल्क व्यवस्था की गयी है और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर हमने कहा था कि इसे हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से कैबिनेट होने में देरी हो गयी।

कैबिनेट न होने के बावजूद हमने नकल विरोधी अध्यादेश को विचलन से महामहिम राज्यपाल को अग्रसारित कर दिया है। यह भी तय कर दिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सभी इस अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सबसे सख्त कानून जो हो सकता है, वो हमने बनाने का काम किया है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास तक की सजा के अलावा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने के सख्त प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने छात्रों, बेटों-बेटियों से कहना चाहते हैं कि सभी परीक्षा पारदर्शी होंगी,किसी भी अफवाहों पर न जाएं, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें, सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और शुचिता के साथ होंगी।

सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर धामी सरकार ने देश में पेश की मिसाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 10 फरवरी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है।देहरादून , 11 फरवरी , उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 09 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए माननीय राज्यपाल की मंजूरी के लिए अग्रसारित किया था। इस अध्यादेश में दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित

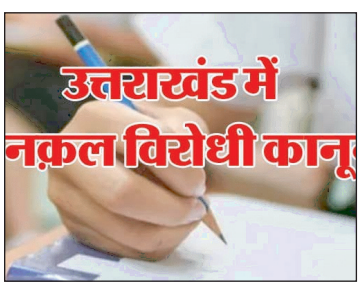

साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में दस वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः पांच से दस वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित सम्पति की कुर्की की जायेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय होगा।

चांद पर कब्ज़ा कर लेगा चीन, सताने लगा डर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 10 फरवरी , पूर्व एस्ट्रोनॉट और मौजूदा नासा चीफ और फ्लोरिडा सीनेटर बिल नेल्सन ने रविवार को एक इंटरव्यू के दौरान यह चेतावनी दी है. बिल नेल्सन ने कहा कि, अगर अमेरिका से पहले चीन ने चांद पर ठीक तरह से अपने पैर जमा लिए तो वहां के अधिकांश संसाधन संपन्न क्षेत्रों पर चीन कब्जा कर लेगा.

साउथ चाइना सी हो या और भी कई इलाके, चीन की हमेशा कब्जा जमाने या उस जगह पर अपना दावा ठोंकने की नीति रही है. ऐसे में नासा को डर है कि कहीं चीन चांद पर जाकर भी अपनी जमीन होने का दावा न कर दे. जी, हां नासा चीफ बिल नेल्सन ने जो कहा है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. नासा चीफ का कहना है कि अगर अमेरिका से पहले चीन ने चांद पर अपने पैर जमा लिए तो वह वहां जाकर भी अपनी जमीन होने का दावा कर देगा. साथ ही दूसरे देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के वहां पहुंचने में मुश्किलें पैदा कर देगा. पूर्व एस्ट्रोनॉट और मौजूदा नासा चीफ और फ्लोरिडा सीनेटर बिल नेल्सन ने रविवार को एक इंटरव्यू के दौरान यह चेतावनी दी है. बिल नेल्सन ने कहा कि, अगर अमेरिका से पहले चीन ने चांद पर ठीक तरह से अपने पैर जमा लिए तो वहां के अधिकांश संसाधन संपन्न क्षेत्रों पर चीन कब्जा कर लेगा.

चीन कह देगा- यह हमारा इलाका है, यहां से बाहर निकलो

नासा चीफ बिल नेल्सन ने कहा कि, ''यह सच है कि हम चीन के साथ स्पेस रेस में हैं. और यह भी सच है कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर चीन चांद पर अपना कब्जा न जमा ले. और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि चीन साफ तौर पर कह दे कि यहां से बाहर रहो, हम यहां पर हैं और यह हमारा इलाका है.'' साल 2022 में चीन अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत नए स्पेस स्टेशन की शुरुआत सफलतापूर्वक कर चुका है. वहीं नासा अभी आर्टेमिस मिशन सीरीज पर काम कर रहा है. 26 दिनों के नासा के आर्टेमिस मिशन 1 को नवंबर में लॉन्च किया गया था. इस मिशन के तहत नासा को चांद की सतह पर जाकर तस्वीरें लेनी हैं.

वहीं आर्टेमिस मिशन सेकेंड और थर्ड पर काम चल रहा है, इनके जरिए चांद की सतह पर और भी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे नासा को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए. नासा का मिशन आर्टेमिस 1 पृथ्वी पर 26 दिनों को पूरा करने के बाद दिसंबर में लौट आया है. दूसरी ओर, मार्स यानी मंगल ग्रह पर भी नासा पूरी तरह फोकस कर रहा है. मंगल गृह की मिट्टी, वातावरण समेत अन्य जानकारियों को लेने के लिए नासा की ओर से कई रोबोटिक रोवर भी भेजे गए हैं. चीन की शी जिनपिंग सरकार अपने स्पेस प्रोग्राम्स पर जमकर पैसा खर्च कर रही है. स्पेस में मजबूती बढ़ाने के लिए चीन लगातार किसी न किसी तरह की कोशिशें कर रहा है. वहीं अमेरिका भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है और लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है.

इम्यूनिटी व नींद का गहरा संबंध, देर रात तक जागने से घटती है इम्यूनिटी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट ,10 फ़रवरी , तापमान में हल्की गिरावट भी इम्यूनिटी को 50 प्रतिशत तक घटा देती हैं। इसका असर नाक पर सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में सर्दी, ज़ुकाम जैसे संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में इनसे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इम्यूनिटी को बढ़ाना और उसे बनाए रखना है।पर्याप्त नींद के साथ ही यदि हेल्दी डाइट, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी और फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखा जाए तो इम्यूनिटी को मजबूत रखा जा सकता है।

सवाल. कमजोर इम्यूनिटी की निशानी क्या है। इसके अलर्ट को कैसे समझें ?

जवाब. बार-बार बीमार पड़ना, बार-बार कोई इन्फेक्शन होना (फेफड़ों , आंतों का या त्वचा का इन्फेक्शन), वजन कम होना, लिवर तिल्ली और लिम्फ नोड्स का बड़ जाना या इम्युनोग्लोबुलिन का कम हो जाना कमजोर इम्यूनिटी के लक्षण हैं।

सवाल. कौन-कौन-से व्यायाम हैं, जिन्हें करने से इम्यूनिटी बढ़ती है?

जवाब. प्रतिदिन 30 से 45 मिनट पैदल घूमना, योग करना या किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलने से इम्यूनिटी बढ़ती है।

सवाल. क्या नींद का इम्यूनिटी से भी संबंध है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए?

जवाब. रिसर्च से पता चला है कि नींद का इम्यून सिस्टम से गहरा संबंध है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेना चाहिए जो लोग रात को देर तक जागे रहते है उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है।

सवाल. अच्छी इम्यूनिटी के लिए खानपान में कौन-सी चीजों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए?

जवाब. कोई विशेष प्रकार के खाने से इम्यून सिस्टम नहीं सुधरता। एक बैलेंस्ड फूड ज़रूर फायदा पहुंचाता है। घर का हिंदुस्तानी ख़ाना श्रेष्ठ है।

सवाल. रोजमर्रा की ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। ऐसे ही कौन सी आदतें इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती हैं?

जवाब. देर तक जागना, शराब और धूम्रपान करना और नकारात्मक सोच ये सब इम्यून सिस्टम को कमजोर करते है। बैलेंस्ड फूड, व्यायाम, योग, पर्याप्त नींद ये सब इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं।

बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल थमाना नुकसानदेह

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

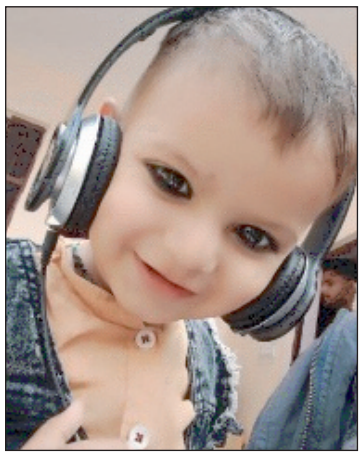

ब्यूरो रिपोर्ट , 10 फ़रवरी , कई बार बच्चे रोते हैं तो पैरेंट्स उन्हें मोबाइल या टैबलेट देकर शांत करा देते हैं। इससे बच्चे उस वक्त तो शांत हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। दरअसल, 9 साल की उम्र पूरी होने के बाद इस तरह के बच्चे जब दूसरे बच्चों के संपर्क बनाते हैं, तो डिवाइस की लत के चलते उन्हें घुलने-मिलने में दिक्कत होती है।उनकी एकाग्रता घटती है और कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है।

स्क्रीन का बच्चों पर असर जानने के लिए हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड में हुए एक शोध हुआ। इसमें सामने आया कि 9 साल की उम्र तक ज्यादा समय मोबाइल या टैबलेट के साथ बिताने वाले बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस घटती है। मानसिक स्वास्थ भी बिगड़ता है। शोध में बताया गया कि ऐसे बच्चों को बचपन में मोबाइल थमाना उनसे बचपन छीनने जैसा होता है। इससे ज्यादा उन्हें बड़ों से बातचीत करने देना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा उन्हें सोशल एक्टिविटी या शारीरिक गतिविधियां कराने की भी जरूरत है, ताकि शारीरिक और मानसिक विकास हो सके।ऐसे बच्चे भावनात्मक रूप से काफी कमजोर होते हैं। इसका असर लड़कों में ज्यादा होता है। एक अन्य शोध के अनुसार स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और वे कई बार चुनौतीपूर्ण माहौल में आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। इससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी तो कम होती ही है।

चिकित्सक ईमानदारी से निभाएं फ़र्ज़ , सरकार जनता के लिए समर्पित : डॉ आर राजेश कुमार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हल्द्वानी , 10 फरवरी , स्वास्थ्य सचिव डा0 आर. राजेश कुमार ने जबसे स्वास्थ्य विभाग का ज़िम्मा सम्हाला है हालात जांचने और सुधारने के लिए वो पहाड़ों में ताबड़तोड़ मुआयना और फील्ड रियलिटी चेक कर रहे हैं। जहां कमियां मिल रही है वहां सख्त चेतावनी औऱ सुधार के आदेश दे रहे हैं , दूसरी तरफ अफसरों और मेडिकल स्टाफ को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सुझाव भी दे रहे हैं। उन्होंने सुशीला तिवारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज तथा महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान डॉ आर राजेश कुमार ने चिकित्सा अधिकारियों को मनोयोग से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा आम जनमानस को सुचारू चिकित्सा उपचार मिल सके यही हमारी प्राथमिकता है।

सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि जिन चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की कमी है जल्द ही तैनाती की जायेगी।

▪ स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कालेज के ऑडिटोरियम के निरीक्षण के दौरान पाया कि कोविड 19 में दौरान डीआरडीओ द्वारा अस्थाई चिकित्सालय स्थापित किया गया था। उक्त चिकित्सालय के बैड, वैंटिलेटर, मल्टीपैरा मशीन आदि आडिटोरियम में पाये गये उन्होंने स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपकरणों की शीघ्र से सूची बनाकर बेस चिकित्सालय पिथौरागढ, मेडिकल कालेज अल्मोडा को भेजने के निर्देश मौके पर दिये। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कालेज हल्द्वानी को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर इस कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने प्राचार्य को निर्देश दिये कि चिकित्सालय के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता हो तो शीघ्र जनहित हेतु उसकी पूर्ति करें। उन्होंने कहा इस हेतु धन की कोई कमी नही होने दी जायेगी। उन्होने प्राचार्य से कहा कि चिकित्सालय से सम्बन्धित जो भी

कार्य हों उन कार्यो को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाना जरूरी है।

▪ सचिव डॉ कुमार ने कहा कि कैंसर हास्पिटल परिसर में बनने वाले नवनिर्माण भवन की जद मे आ रहे पेड की अनुमति एवं आपत्तिों का शीघ्र निराकरण हेतु वन विभाग से कार्यवाही की जायेगी ताकि निर्माण कार्यो को समय से प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस हेतु 160 चिकित्सालय के स्टाप की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। डॉ आर राजेश कुमार द्वारा कैंसर चिकित्सालय के ओपीडी, के साथ ही सुशीला तिवारी चिकित्सालय मे कॉडियोलॉजी, जनरल वार्ड, आईसीयू, ओपीडी, डायलेशिस के साथ ही भर्ती मरीजों से रूबरू हुये तथा उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उनके द्वारा अटल आयुष्मान कार्ड काउन्टर का भी निरीक्षण किया गया।

इसके पश्चात सचिव द्वारा महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। महिला चिकित्सालय मे कुमार द्वारा ओपीडी, वार्ड के साथ ही मरीजों से मिले। निरीक्षण दौरान प्राचार्य डा0 अरूण जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भागीरथी जोशी, प्राचार्य पिथौरागढ डा0 अरविन्द, संयुक्त निदेशक डा0 महेन्द्र कुमार, डा0 एमके पंत,जनसम्पर्क अधिकारी आलोक उप्रेती के साथ ही स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी उपस्थित थे।

ACS आनंद वर्धन ने ली सभी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग की अहम बैठक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 10 फरवरी , अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन ने राज्य में संचालित सभी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु एक इंटिग्रेटेड सिस्टम विकसित करने के साथ ही सिंगल पोर्टल बनाने हेतु उद्योग विभाग के नेतृत्व में पर्यटन विभाग तथा शीर्ष बैंको की पांच सदस्यी उप समिति गठित करने के निर्देश दिए है।

अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना (होम स्टे), पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो), मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैंक प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य 6000 के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 6173 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 103 प्रतिशत है। बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे 28 फरवरी 2023 तक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण तथा स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिसम्बर माह तक वार्षिक लक्ष्य 1783 के सापेक्ष 1867 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गए, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 105 प्रतिशत है। होम स्टे योजना (वीसीएसजीएसवाई) के तहत वर्ष 2022-23 के माह दिसम्बर तक बैंकों द्वारा वाहन मद में निर्धारित लक्ष्य 150 के सापेक्ष 156 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 104 प्रतिशत है तथा गैर वाहन मद में निर्धारित लक्ष्य 100 के सापेक्ष 59 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 59 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में बैंकों को लम्बित ऋण आवेदन 28 फरवरी 2023 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दिसम्बर माह तक बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 200 के सापेक्ष 139 आवेदकों को ऋण वितरित किए गए हैं। इस संबंध में बैंकों को ऐसे ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें सेक्शन 143 अंतर्गत अकृषि प्रमाण पत्र एवं निर्माणधीन इकाई का मानचित्र अधिकृत एजेन्सी से स्वीकृति की आवश्यकता नही हैं। बैंक प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करने की समय सीमा दिसम्बर माह 2024 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दिसम्बर माह 2022 तक 217258 लाभार्थियों को निर्धारित लक्ष्य 2500 करोड़ रूपये के सापेक्ष 2173.51 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं, जोकि लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। योजना के तहत अनुमानतः 307174 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ऋण के गारंटी कवर लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

बैठक में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) 2019-2024 जिसमें नई बैंक शाखाएं खोलने, बैंकिग सेवाओं से अनाच्छादित गांवों, बिजनेस कॉरोस्पोन्डेट तथा कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करने एवं सामाजिक सुरक्षा योजना पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बैंकिग सेवा रहित 80 गांवों में डीसीबी द्वारा सेवाएं देने में असमर्थ होने की स्थिति में शीर्षस्थ बैंकों को इस दिशा में पहल करनी होगी। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को मजबूत करने तथा विस्तार देने के लिए अल्मोड़ा तथा चमोली जिले में अच्छा काम हुआ है। अब पिथौरागढ़ तथा पौड़ी जनपद में इस दिशा में काम किया जाना चाहिए।बैठक में अपर सचिव पर्यटन पूजा गबयार्ल, अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पांडे, सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति नरेंद्र सिंह रावत, मीनाक्षी सहायक महाप्रबंधक आरबीआई, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

चार धाम यात्रा : हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर नया प्लान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड 10 फ़रवरी , बस कुछ ही महीनों के बाद में केदारनाथ यात्रा दोबारा से संचालित की जाएगी जिसको लेकर लोगों के बीच में उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है। इस बीच हेली कंपनियों ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। सभी हेली कंपनियां तीन वर्ष के लिए अनुमानित किराया बताएंगी। बता दें कि हेली सेवाएं पिछले कई वर्षों से लोगों के लिए एक वरदान के रूप में सामने आई हैं। खासकर कि बुजुर्ग, गर्भवती स्त्रियां और छोटे बच्चों के लिए लोग हेलीपैड ही पसंद करते हैं। ऐसे में अब चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (यूकाडा) ने केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में हेली सेवा संचालन को टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस टेंडर प्रक्रिया में सभी हेली कंपनियां तीन वर्ष के लिए अनुमानित किराया बताएंगी। टेंडर में दर्ज किराये का अध्ययन करने के बाद हेली सेवाओं का किराया तय किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में हर साल चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवाएं संचालित होती हैं। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं केदारघाटी के फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड से संचालित की जाती हैं। दूरी के हिसाब से इनका किराया तय किया जाता है। हेली कंपनियों को संचालन की अनुमति देने से पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की टीम हेलीपैड का मौका मुआयना करती हैं। व्यवस्था सही पाए जाने के बाद ही हेली कंपनियों का किराया तय किया जाता है। अप्रैल में शासन हेली सेवाओं के लिए बुकिंग शुरू कर देता है। बता दें कि शासन ने वर्ष 2019 में तीन साल के लिए टेंडर किए गए थे जिसमें यह तय किया गया था कि तीन साल तक हेली सेवा का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। इस वर्ष अनुबंध की सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में नागरिक उड्डयन विभाग ने नए सिरे से किराया तय करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं।

अल्मोड़ा के झड़गांव में महिला को बाघ ने उतारा मौत के घाट

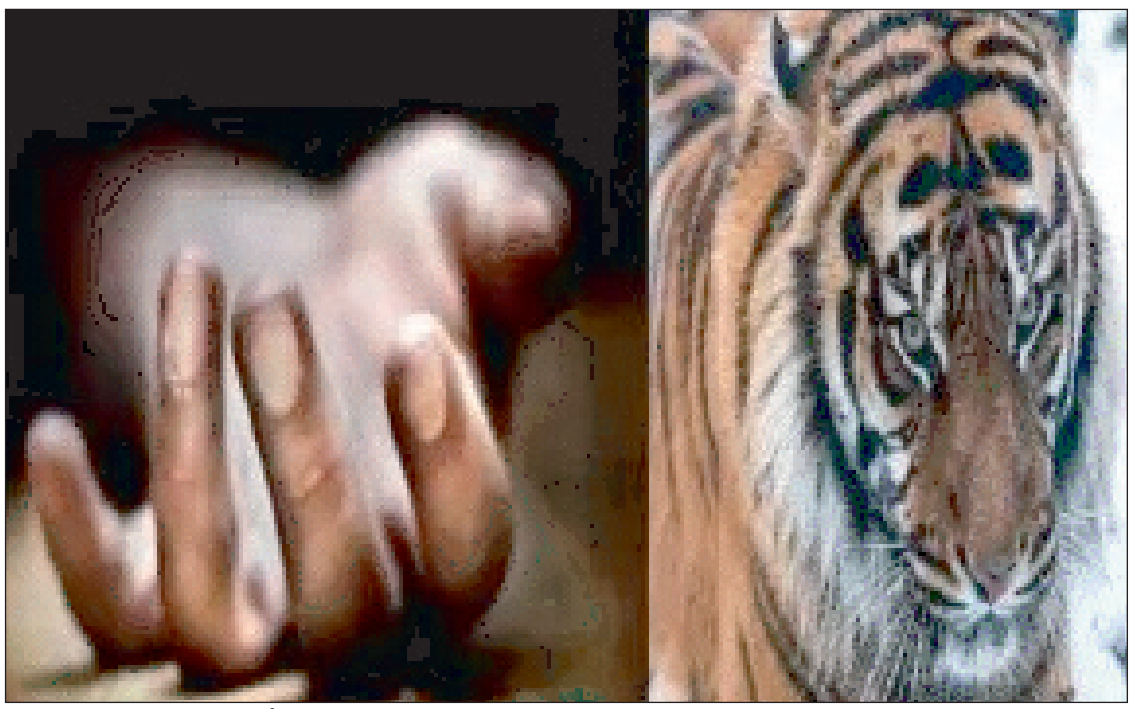

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अल्मोड़ा 10 फ़रवरी , मरचूला के झड़गांव में महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। बीते दिन घास लेने जंगल गई महिला का शव दूसरे दिन घर से महज 300 मीटर दूर मिला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है। वन विभाग ने बाघ के हमले में मौत की पुष्टि की है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ पौड़ी-रामनगर एनएच छह घंटे तक जाम कर दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, एक करोड़ मुआवजा, बाघ को मारने के आदेश जारी करने की मांग की। किसी तरह प्रशासन ने ग्रामीणों से वार्ता कर ग्रामीणों को जाम से उठाया।सल्ट मरचूला के पास झड़गांव में जंगल गई कमला देवी पत्नी यशवंत बीते दिन को घर नहीं लौटी। प्रशासन, वन विभाग की टीम व ग्रामीण पूरी रात खोजबीन में जंगलों की खाक छानते रहे। दूसरे दिन घर से 300 मीटर दूर एक खेत में महिला का शव मिला तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला के गले व चेहरे पर गहरे निशान मिले। पुलिस ने शव का पंचनामा भरा, मगर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की बात सुनते ही ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में बाघ का आतंक बना हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। लेकिन इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसकी कीमत महिला को जान गंवाकर चुकानी पड़ी है।

अल्मोड़ा 11 फ़रवरी , मरचूला के झड़गांव में महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। बीते दिन घास लेने जंगल गई महिला का शव दूसरे दिन घर से महज 300 मीटर दूर मिला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है। वन विभाग ने बाघ के हमले में मौत की पुष्टि की है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ पौड़ी-रामनगर एनएच छह घंटे तक जाम कर दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, एक करोड़ मुआवजा, बाघ को मारने के आदेश जारी करने की मांग की।

किसी तरह प्रशासन ने ग्रामीणों से वार्ता कर ग्रामीणों को जाम से उठाया।सल्ट मरचूला के पास झड़गांव में जंगल गई कमला देवी पत्नी यशवंत बीते दिन को घर नहीं लौटी। प्रशासन, वन विभाग की टीम व ग्रामीण पूरी रात खोजबीन में जंगलों की खाक छानते रहे। दूसरे दिन घर से 300 मीटर दूर एक खेत में महिला का शव मिला तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला के गले व चेहरे पर गहरे निशान मिले। पुलिस ने शव का पंचनामा भरा, मगर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की बात सुनते ही ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में बाघ का आतंक बना हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। लेकिन इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसकी कीमत महिला को जान गंवाकर चुकानी पड़ी है।

यहां दुकानों पर नहीं होते हैं दुकानदार, भरोसे पर सालों से चल रही हैं शॉप्स

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट ,10 फ़रवरी , कभी कोई सामान खरीदना हो तो हम सबसे पहले इससे संबंधित शॉप पर जाते हैं और शॉपकीपर से अपनी जरूरत की कीमत चुका कर सामान खरीद लेते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन शॉपिंग भी एक विकल्प है। इसमे एक क्लिक करके संबंधित प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पेमेंट से कोई भी चीज आप घर बैठे ऑर्डर सकते हैं। इससे इतर कभी आपने सोचा कि आप किसी दुकान पर पहुंचे, जहां कोई दुकानदार ही न मिले। बस आप जाएं और वहां अपने हिसाब से चीज लें और उस सामान के पैसे वहीं पास में रखे थैले या बॉक्स में रखकर चले जाएं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर ऐसा है। कहीं और नहीं बल्कि अपने देश में ही भरोसे के दम पर दुकानें चल रही हैं। कहां ये शॉप्स और कैसे होती हैं संचालित, आइए जानते हैं।

ये दुकाने मिजोरम में मौजूद है। राजधानी आइजोल से 11 किलोमीटर से दूर सेलिंग में सड़क किनारे कई ऐसी दुकानें हैं, जहां पर शॉपकीपर नहीं होते हैं। यहां कई फल, सब्जी समेत अन्य चीजों की दुकानें हैं, जहां पर दुकानदार पैसे लेने के लिए मौजूद नहीं होते हैं। न ही कोई तोल-मोल होता है। बस ग्राहक आपकी जरूरत के हिसाब से सामान लेते हैं और उसके पैसे पास में रखे थैले या बॉक्स में रखकर चले जाते हैं। बिना दुकानदारों की दुकानों को मिजोरम की स्थानीय भाषा में 'नगाह लोह द्वार' कहा जाता है। यह शॉप्स किसान लगाते हैं, जो कि खेती करने के साथ-साथ ये फल, सब्जी की दुकान भी लगाते हैं। ये दुकान पर भले ही कोई शॉपकीपर देखने वाला नहीं है लेकिन फिर भी यहां कभी कोई चीज चोरी नहीं होती है। इसी तरह कोई भी दुकानों पर लगे बॉक्स से कोई पैसे उठाकर नहीं ले जाता है, बल्कि इन दुकान के मालिकों को पूरे पैसे मिलते हैं। यहां दुकाने पूरी तरह भरोसे पर चलती हैं। यह दुकाने सालों से चल रही हैं।

केदारनाथ यात्रा में दें यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं : धन सिंह

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुद्रप्रयाग, 10 फरवरी । केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने अफसरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।

कलक्ट्रेट सभागार में यात्रा तैयारी एवं व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि केदारनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। इसके लिए गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में हर एक किमी की दूरी में एमआरपी (मेडिकल रिलीफ पोस्ट) स्थापित किए जाएं। यहां पर्याप्त स्टाफ के साथ ही दवा एवं जरूरी उपकरण रखे जाएं। सभी एमआरपी में ऑक्सीजन कंसंटेटर की भी व्यवस्था की कराई जाए। केदारघाटी क्षेत्र में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए गुप्तकाशी में उप जिला चिकित्सालय खोले जाने के लिए भी भूमि चिन्हित करने के साथ ही जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सोनप्रयाग में स्थाई चिकित्सालय तैयार किए जाने के लिए भी भूमि का चयन करने, यात्रा मार्ग में पयाप्त मात्रा में एंबुलेंस व्यवस्था भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि जरूरत पडने पर मरीज को तत्काल चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा जा सके।

मंत्री ने केदारनाथ धाम में बन रहे चिकित्सालय के निर्माण को शीघ्र पूरा करने, जिन चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था नहीं है ऐसे, चिकित्सालयों में आवास बनाए जाने के लिए प्रस्ताव बनाने, यात्रा मार्ग में भी यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित करने, केदारनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पचास बड़े होर्डिंग एवं सौ छोटे होर्डिंग लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियुगीनारायण, तुंगनाथ आदि धार्मिक स्थलों में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी सभी चिकित्सा सुविधा देने को कहा। धन सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सभी सुविधाएं एवं विभागीय स्तर पर धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। चारधाम यात्रा को बेहतर संचालित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जो भी दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं उनका पालन कराते हुए केदारनाथ यात्रा को बेहतर संचालित किया जाएगा।

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एचसीएस मार्तोलिया ने केदारनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग में की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं एवं डॉक्टर व स्टाफ तैनात किए जाने की जानकारी दी। केदारनाथ में तैनात किए जाने वाले डाक्टर तैनात किए जाएंगे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चैधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पंवार, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कप्रवाण, सीडीओ नरेश कुमार, एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी, सीएमएस डॉ राजीव सिंह पाल, सीईओ विनोद प्रसाद सिमल्टी,डॉ आशुतोष, डॉ शशि आदि मौजूद थे।

पटवारी परीक्षा तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी ने की बैठक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चमोली, 10 फरवरी । उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 12 फरवरी, रविवार को आयोजित होने वाली राजस्व उप उपनिरीक्षक पटवारी/लेखपाल परीक्षा की तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी डा. अभिषेक त्रिपाठी ने सभी नोडल अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं केन्द्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए। सभी केन्द्रों पर परीक्षा से एक दिन पूर्व ब्रीफिंग की जाए और अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी परीक्षा केन्द्रों पर वीडियोग्राफी की जाए।

उन्होंने बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल परीक्षा के लिए जनपद में 18 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है, जिसमें कुल 4748 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केन्द्र में घड़ी, स्मार्ट वाच, मोबाइल फोन एवं गैजेट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस को परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा टीमों को अलर्ट रखने के निर्देश दिए

गए। अपर जिलाधिकारी ने नियुक्त सभी अधिकारियों को संवदेनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षा को संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही अभ्यर्थियों से 9.30 बजे तक परीक्षा केन्द्र में पहुंचने की अपील की। परीक्षा 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भोजनमाताओं ने की शिक्षा महानिदेशक से 8 हजार मानदेय दिए जाने की मांग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

विकासनगर, 10 फरवरी । प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत भोजनमाताओं ने शिक्षा महानिदेशक से मानदेय बढ़ाए जाने समेत कई अन्य लंबित मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को महानिदेशालय पहुंचे भोजनमाता संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने इस आशय का ज्ञापन महानिदेशक को सौंपा। ज्ञापन सौंपने महानिदेशालय पहुंची भोजनमाता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष उषा देवी ने बताया कि बीस वर्ष से अधिक समय से सरकारी विद्यालयों में भोजनमाताएं अपनी सेवा दे रही हैं, लेकिन उन्हें अभी अल्प मानदेय दिया जा रहा है। इस मानदेय में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल होता है। लिहाजा भोजनमाता का मानदेय आठ हजार रुपए प्रतिमाह किया जाना चाहिए। 65 से 70 वर्ष की आयु में भोजनमाताओं उनकी सेवा के अनुसार एक सम्मानजनक राशि देकर सेवानिवृत्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कहा कि कुछ विद्यालयों में भोजनमाताओं से साफ सफाई का कार्य लिया जा रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। बताया कि भोजनमाताओं को प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोडक़र पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा कवच मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निरंतर कम हो रही छात्र संख्या के कारण भोजनमाता की सेवा समाप्त नहीं करने, मैदानी क्षेत्र के सभी विद्यालयों को अक्षय पात्र योजना से जोडने, मानदेय सीधे बैंक खाते के माध्यम से दिए जाने की मांग भी शिक्षा महानिदेशक से की है। प्रतिनिधि मंडल में संगठन के संरक्षक जगदीश गुप्ता, संसारवती, बसंती आदि शामिल रहे।

संक्षप्ति खबरें

एकेश्वर ब्लाक में हुआ बहुद्देशीय शिविर का आयोजन

पौड़ी। एकेश्वर ब्लाक में समाज कल्याण विभाग, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में बहुउदेश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे बाल विकास, खाद्य आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लाक प्रमुख एकेश्वर दीपक पांथरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी योगेंद्र नेगी ने ब्लाक स्तर पर चल रही समस्त योजनाओं की जानकारी दी। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पौड़ी के नोडल अधिकारी धर्मेंद्र पंवार ने दिव्यांगो के पुनर्वास एवम रोजगार के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की। शिविर में कुल 138 आवेदन आए। मानसिक दिव्यांगो के 13 व अन्य दिव्यांग प्रमाणपत्र के 44 आवेदन आए। कार्यकर्म में खंड विकास अधिकारी योगेश नेगी , ब्लाक प्रमुख एकेश्वर नीरज पंथरी , जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सजवान आदि शामिल थे।

महाशिवरात्रि को लेकर व्यवस्थाएं होंगी चाकचौबंद

हरिद्वार। महाशिवरात्रि के चलते कावडियों का हरिद्वार आना शुरू हो गया है। 18 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पुरी तरह कमर कस ली है। चंडीघाट पुल से चिडियापुर सीमा तक कावड़ के लिए हाईवे पर गड्ढों की मरम्मत और आवश्यक स्थानों पर पेयजल, ऊर्जा विभाग सडक़ रोशनी जैसी सुविधाओं को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्वी गंगानहर पटरी पर सफाई अभियान चलाया गया। एनएच हाईवे प्रशासन यातायात और कावड़ को वनवे व्यवस्था करने पर जुटा है। पुलिस की ओर से ट्रैफिक और शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी मांग की गई है। चिकित्सा विभाग द्वारा कावड़ रूट पर मेडिकल कैम्प की व्यवस्था की जाएगी। शारदीय महाशिवरात्रि कावड़ मेले मे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत आदि जिलों से लाखों की संख्या मे कावडिये आते हैं। जिसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा है। एसपीसिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि कांवड़ मेला सम्पन्न कराने को लेकर श्यामपुर क्षेत्र मे चंडी पुल से चिडियापुर सीमा तक सडक़, पेयजल, पथ प्रकाश, चिकित्सा, यातायत आदि व्यवस्था को सभी संबंधित विभागों को आदेशित कर दिया गया है।

मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने हेतु हुई कार्यशाला

हरिद्वार। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चीला रेंज में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। पूर्व में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई दफा इस कारण वन्यजीवों की मृत्यु हो चुकी है। शुक्रवार को चीला प्रशिक्षण केंद्र में अंतर्विभागीय समन्यवय और जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्यवय स्थापित किया गया। साथ ही जागरूकता के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान अपर प्रमुख वन संरक्षक आरके मिश्रा ने कहा कि बाघ, हाथी एवं अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए बायो कॉउटस्टिक्स, रेडियो कॉलर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सेटेलाइट अपलिंक जैसी सुविधाओं पर आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। राजाजी के निदेशक डॉ.साकेत बडोला ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान के उपयोग अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों की सहभागिता तथा मानव वन्यजीव संघर्ष परिस्थितियों का प्रबंधन करने में विशेषज्ञता रखने वाले प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। राजा जी की उपनिदेशक कहकशां नसीम ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला के आयोजनों के माध्यम से सभी विभागों से आपसी समनव्य बनाकर मानव और वन्यजीव संघर्षों को काफी हद तक टाला जा सकता है। चीला रेंज के रेंजर शैलेस घिल्डियाल, डॉ.योगेश शर्मा, जिला आपदा अधिकारी मीरा कैंथुरा, एसडी पंत, प्रशांत, सोमांश गुप्ता, अरुण कंडारी, चंद्रशेखर, चरण सिंह, प्रवीन रावत, सोमपाल सिंह, मोहित आदि अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

दूधमुंहे बेटे की खरीद फरोख्त में मां, नाना समेत चार गिरफ्तार

हरिद्वार। मां-बेटे के रिश्ते को कलंकित करते हुए एक मां अपने पिता के साथ मिलकर अपने दूधमुंहे बेटे का सौदा कर दिया। हरकत में आई कनखल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मां, नाना, खरीदार युवक और सौदे में मध्यस्ता करा रही उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने मासूम को खरीदने के लिए लाई गई पांच लाख की रकम भी बरामद कर ली है। एसएसपी अजय सिंह ने कनखल पुलिस की पीठ थपथपाई है।

नर्सिंग अधिकारी पद पर उत्तराखंड के युवाओं को ही दें मौका

अल्मोड़ा। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों पर केवल उत्तराखंड के ही बेरोजगार युवाओं को ही मौका देने की मांग की है। मामले शुक्रवार को बेरोजगार युवाओं ने अल्मोड़ा में डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा कि उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की ओर से नर्सिंग अधिकारी पद पर मौका देने को लेकर उच्च न्यायालय की शरण ली। जिसमें न्यायालय की ओर से उन्हें फार्म भरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। युवाओं ने कहा कि बाहरी राज्य के लोगों को भर्ती में मौका दिए जाना उत्तराखंड के मूल निवासियों का हक छीनने की तरह है। युवाओं ने एक स्वर में नर्सिंग अधिकारी पद पर केवल उत्तराखंड के युवाओं को ही मौका देने की मांग की है। मांग पूरी नही होने पर युवाओं ने आंदोलन की भी चेतावनी दी। यहां महासंघ के सचिव गोविंद सिंह रावत, पूजा पांडे, गौरव, बबीता, भावना, अनीता, नरेश आदि मौजूद रहे।

चरस और गांजा पाउडर के एक व्यक्ति गिरफ्तार

अल्मोड़ा। एसओजी और लमगड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को मोरनौला चौकी पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान चम्पावत देवीधुरा मोटरमार्ग की ओर से आ रहे आशिक अली उर्फ भूरा पुत्र बाबू खां, निवासी ग्राम नरऊ, थाना पासऊ, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर के कब्जे से 151 ग्राम चरस और 1.235 किलो गांजा पाउडर बरामद किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। टीम में मोरनौला चौकी प्रभारी एसआई संजय जोशी, हेड कांस्टेबल मनोज क्वीरा, सिपाही बिशन बिष्ट रहे।

सारे अपराधों की जड़ है नशा : जोशी

बागेश्वर। नशे को ना जिंदगी को हां की थीम पर नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रही मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारक समिति अपने अभियान को जारी रखते हुए शुक्रवार को खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज गरुड़ में पहुंची। जहां मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने स्कूली छात्र-छात्राओं से युवा संवाद के जरिए नशे से दूर रहने की अपील की। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जोशी ने कहा कि नशा ही सारे अपराधों की जननी है। कहा कि जिस देश का युवा नशे की गिरफ्त में होगा, फिर उस देश के लिए एक समर्थ राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है।

रामगढ़ राजकीय उद्यान पार्क की जमीन सिडकुल को देना भृष्टाचार : यशपाल आर्य

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

11 फरवरी , रामगढ़ में उद्यान विभाग की 4.4 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के खिलाफ ग्रामीणों, व्यापारियों, किसानों द्वारा आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन अनशन प्रदर्शन चल रहा है ।नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रामगढ़ राजकीय उद्यान पार्क की जमीन को सिडकुल को दिए जाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग की आंख कहे जाने वाले रामगढ़ राजकीय उद्यान की जमीन को सिडकुल जैसी कंपनियों के हाथों में दिया जाना सरकार का गलत निर्णय है. इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा की रामगढ़ की उद्यान विभाग की जिस भूमि को फल पट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है उसी भूमि को सिडकुल को निशुल्क हस्तांतरित करना सरकार और शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

रामगढ़ में बाहरी उद्योगपतियों को लाकर होटल खोलने की योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा ।यशपाल आर्य ने कहा की उत्तराखंड का निर्माण हिमाचल की तर्ज पर विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन सरकार भूमि व संसाधनों को बेचने का काम कर रही हैं. यहां भौगोलिक क्षेत्र होने से पर्यटक हमेशा आता है, सरकार फ्रुट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कार्य करे. सरकार इस क्षेत्र को भी जोशीमठ व केदारनाथ बनाने की तैयारी कर रही है. उद्यान की 4.4 एकड़ जमीन जनता को छलकर हस्तांतरित कर दी.

ईमानदारी व्यापारी और कर्मठ अफसर-कर्मचारी भी होंगे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, र, 10 फरवरी । आज बाजार से जो भी सामान खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें। ये आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और प्रदेश के विकास के लिए भी। शुक्रवार को राज्य कर मुख्यालय में 'बिल लाओ ईनाम पाओ' के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह अपील की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उपभोक्ताओं को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार ईमानदार व्यापारियों और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है। यहां कई चुनौतियां हैं। राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व बढ़ाया जाना भी बेहद जरूरी है। राज्य केवित्तीय संसाधनों में जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आम तौर पर खरीदारी के बाद पक्का बिल लेना आम आदमी के स्वभाव में नहीं है। लेकिन अब इसे आदत में शामिल करना होगा। उन्होंने बताया पिछले साल वर्ष 2021-22 में जनवरी तक 4625 करोड़ का राजस्व मिला था। जबकि इस साल यह बढक़र 6236 करोड़ रुपये हो चुका है। पिछले साल के मुकाबले यह 35 फीसदी ज्यादा है। राज्य कर आयुक्त डॉ.अहमद इकबाल ने कहा कि राज्य के राजस्व में जीएसटी का योगदान सबसे ज्यादा है। राजस्व अधिक होने पर राज्य के विकास की राह भी सशक्त होती है। इस विकास में देश के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी भी जरूरी है। इसलिए जब भी खरीदारी करें तो पक्का बिल अवश्य लें। इस मौके पर अपर आयुक्त आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त अनिल सिंह, अपर आयुक्त अमित गुप्ता, संयुक्त कर आयुक्त राकेश वर्मा, सुनीता पांडे, प्रवीण गुप्ता, अनुराग मिश्रा, एसएस तिरुवा, आदि मौजूद रहे।

दीवाली पर होगा मेगा ड्राः वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना में अब तक 18 हजार 655 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए हैं। इनके द्वारा 28 हजार 893 बिल अपलोड किये गये हैं। तीसरा लकी ड्रॉ दिनांक 13 फरवरी, 2023 को प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि विजेताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है। इससे जानकारियां ली जा सकती हैं।

जूनियर इंजीनियर्स ने की 2015 के विवादित प्रमोशन की जांच की मांग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, र, 10 फरवरी । उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने ऊर्जा निगम में 2015 में अधिशासी अभियंता के पदों पर हुए प्रमोशन पर सवाल उठाए। सीएम को भेजे पत्र में मैनेजमेंट की भूमिका को संदिग्ध करार दिया। कहा कि रातों रात वरिष्ठता निर्धारित प्रमोशन कर दिए गए। जबकि डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रमोशन के मामले में पेंच फंसाए जा रहे हैं। इन मामलों की जांच कराई जाए। केंद्रीय अध्यक्ष जेसी पंत ने कहा कि तीनों ऊर्जा निगमों में यूपी की अभियंता सेवा नियमावली लागू है। इसके बाद भी अलग अलग व्याख्या किए जाने के कारण बेवजह के विवाद खड़े हो रहे हैं। जेई सेलेक्शन ग्रेड का तीनों निगमों में कोई स्वीकृत पद नहीं है। ऐसे में कैसे इस पद पर प्रमोशन हो सकते हैं। जिस पद पर प्रमोशन नहीं हो सकते, उस पर काम करने की बाध्यता कैसे हो सकती है। स्वीकृत पदों से अधिक भर्ती किए गए एई की वरिष्ठता नियमावली कैसे निर्धारित की जाएगी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट 19 नवम्बर 2019 में साफ कह चुका है कि किसी को भी उस समय की वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा सकता, जब वो विभाग में आया ही न हो। ऐसे में क्या ये आदेश यूपीसीएल में लागू नहीं होता। कहा कि वर्ष 2018 में हुई डीपीसी में जिन एई की एसीआर न होने के कारण प्रमोशन नहीं हो पाए, उन्हें 2018 से प्रमोशन का लाभ दिया जाए। एक्सईएन के खाली पदों पर कोर्ट के निर्देशानुसार प्रतिबंधित प्रमोशन किए जाएं। एचआर में कार्मिक और विधि विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। कोर्ट के फैसले के विरूद्ध की गई प्रभारी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। विवादित मामलों की जांच कराई जाए।

पुरानी पेंशन बहाली को 19 फरवरी को हल्द्वानी में महारैली

देहरादून। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के बैनर तले 19 फरवरी को हल्द्वानी में महारैली का आयोजन होगा। पुरानी पेंशन बहाली को सरकार पर दबाव तेज किया जाएगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा और महामंत्री सीताराम पोखरियाल ने कहा कि एक अक्तूबर 2005 के बाद कर्मचारियों के लिए पुरानी जीपीएफ पेंशन योजना समाप्त कर नवीन पेंशन योजना लागू की गई। पूरे सेवाकाल में कर्मचारी का काटा गया अंशदान पूरी तरह बाजार में शेयरों पर लगा दिया गया।

एनपीएस ने कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में ला दिया है। रिटायर होने के बाद अब कर्मचारियों को महज 500 रूपये से 1000 रूपये तक पेंशन मिल रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे सकती है, क्योंकि केंद्र ने इस योजना को अनिवार्य नहीं किया है।

संक्षप्ति खबरें

बारिश से पछुवादून में मौसम हुआ सर्द, किसानों, बागवानों के चेहरे खिले

विकासनगर। पछुवादून, जौनसार बावर में शुक्रवार को दिन भर मौसम पल-पल रंग बदलता रहा। पछुवादून में सुबह आसमान हल्के बादलों के बीच धूप भी खिली रही। दोपहर 12 बजे अचानक तेज बारिश के साथ ही हल्की ओलावृष्टि भी हुई। जबकि चकराता में सुबह से ही बादल छाए रहने के बावजूद सिर्फ हल्की बौछारें पड़ीं। हालांकि त्यूणी क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों और बागवानों के चेहरों पर खुशी छा गई। शुक्रवार सुबह दस बजे पछुवादून क्षेत्र में आसमान में काले बादल उमडने लगे। आधा घंटे तक आसमान में बादलों की तेज गडग़ड़ाहट होती रही। ऐसा लग रहा था मानो भीषण बारिश शुरु हो जाएगी। काले बादलों के कारण दस बजे सुबह अंधेरा छा गया था, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसर गया। साढ़े दस बजे के करीब हल्की बूंदाबांदी होने के बाद कुछ देर में मौसम साफ हाने लगा। 12 बजे अचानक फिर आसमान में काले बादल छा गए और तेज बौछार के साथ बारिश शुरु हुई, जिसके बाद ओलावृष्टि हुई। करीब पंद्रह मिनट तक ओले गिरते रहे। हालांकि छोटे आकार के ओले पडने से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं, त्यूणी क्षेत्र में बारिश होने से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए। वहीं बारिश से पछुवादून में बीते सप्ताह से लगातार बढ़ रहे तापमान में गिरावट आ गई, जिससे एक बार फिर ठिठुरन बढ़ गई है।

लाठीचार्ज को लेकर तीर्थनगरी में उबाल-

ऋषिकेश। देहरादून में हुए लाठी चार्ज को लेकर तीर्थनगरी के युवाओं में भी उबाल है। शुक्रवार को ऋषिकेश, डोईवाला, श्यामपुर, मुनिकीरेती में युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। बेरोजगारों ने हाथों में गुलाब लेकर मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। उन्होंने भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच करने की मांग की। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन के समक्ष प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि बीते दो दिनों से उत्तराखंड के बेरोजगार युवा गांधी पार्क में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इन युवाओं पर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस ने बर्बरता पूवर्क लाठीचार्ज किया है, जो निंदनीय है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सन्नी प्रजापति ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। यूकां के विधानसभा अध्यक्ष गौरव राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के साथ बर्बरता की गई है, जो बेहद शर्मनाक है। सरकार हिटलरशाही दिखा रही है। प्रदर्शन करने वालों में दीपक जाटव, मदन मोहन शर्मा, शैलेंद्र बिष्ट, महंत विनय सारस्वत, ललित मोहन मिश्रा, पार्षद देवेंद्र प्रजापति, पार्षद राधा रमोला, पार्षद शकुंतला शर्मा, पार्षद जगत सिंह नेगी, जतिन जाटव, मुकेश जाटव, सरोजनी थपलियाल, संजय शर्मा, विक्रम भंडारी, राजेंद्र कोठारी, हरि सिंह नेगी, हरि राम वर्मा, प्रवीन जाटव, मनीष जाटव, कार्तिक, आशीष, अभिषेक पाल, हिमांशु जाटव, राहुल, अमन कुमार, आदित्य पाल, राजेश, प्रियांशु सारस्वत, रविंद्र यादव, सावित्री देवी, सूरज विश्नोई, बैसाख सिंह पयाल, विजय अग्रवाल, कमल बनर्जी, सिंह राज पोसवाल, रामकुमार भतालिये, अशोक शर्मा, संदीप कुमार आदि शामिल रहे। उधर, श्यामपुर बाईपास में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्यामपुर के अध्यक्ष विजयपाल रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वालों में देवी प्रसाद व्यास, मनोज गोसाई, गब्बर सिंह कैंतुरा, भगवती प्रसाद सेमवाल, धर्मानंद लखेड़ा, कुलदीप असवाल, रतन देव रियाल, सत्येंद्र रावत, बलदेव सिंह नेगी, शोभा भट्ट, शोभा बहुगुणा, योगराज नौटियाल, श्याम लाल, धनीराम, आदि शामिल रहे।

डीएम ने दिए डीपीआरओ के वेतन रोकने के निर्देश

रुद्रप्रयाग। जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में डीएम ने मयाली एवं मनसूना में कंपेक्टर मशीनों का कार्य शुरू न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आम जनता से नदी में कूड़ा न फेंकने का भी आह्वान किया। कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जनपद में अवस्थित नदियों की बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था की जाए। नदियों में किसी भी दशा में आम जनमानस द्वारा कूड़ा-करकट न फेंका जाए। उन्होंने जनपद के घाटों में बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए। नदियों के संवर्धन एवं सरंक्षण के लिए नदियों के किनारे वृहद वृक्षारोपण पर जोर देते हुए जरूरी प्लान बनाने के को कहा।

ऊखीमठ में युकां ने किया प्रदर्शन

रुद्रप्रयाग। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा मुख्य बाजार ऊखीमठ में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जबकि बस अड्डे पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। यूथ कांग्रेस के केदारनाथ विधानसभा अध्यक्ष कर्मवीर कुंवर, ब्लाक अध्यक्ष राकेश नेगी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रीता पुष्पवान, पीसीसी सदस्य आनंद सिंह रावत ने कहा कि अपने हकों के लिए लड़ रहे छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है।

15 अप्रैल तक पूरी करें अफसर केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाएं

न्यूज वायरस नेटवर्क

रुद्रप्रयागर, 10 फरवरी । इस साल की केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सफल संचालित करने के लिए की जाने वाली तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अफसरों की बैठक लेते हुए 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से सभी व्यवस्थाएं बहाल करने के निर्देश दिए। कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने डीडीएमए के अधिशासी अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग में जो भी कार्य किए जाने हैं उन कार्यो को 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए। मार्ग पर रेलिंग लगाने और यात्री शेड बनाने का कार्य पूरा किया जाए।

यात्री वाहनों के लिए सीतापुर और अन्य स्थानों पर पार्किंग के लिए जो टेंडर प्रक्रिया की जानी हैं उसे मार्च प्रथम सप्ताह तक पूरा किया जाए। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा यात्रा मार्ग एवं केदारनाथ धाम में शौचालय निर्माण का कार्य भी निर्धारित तिथि 15 अप्रैल तक पूरा कर ले। साथ ही शौचालयों की सफाई व्यवस्था के लिए समय पर कर्मचारियों की तैनाती की जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को यात्रा मार्ग में संचालित होने वाले घोड़े-खच्चरों के लिए एसओपी तैयार करने, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को डंडी-कंडी हॉकरों के भी अनिवार्य रूप से परिचय-पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि बिना परिचय-पत्र के डंडी-कंडी संचालकों, घोड़ा-खच्चरों हॉकरों एवं मालिकों को आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी साथ कार्रवाई भी होगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, जल संस्थान को पानी की आपूर्ति सुचारु करने, घोड़े-खच्चरों के लिए गरम पानी की चरियों की व्यवस्था, मार्ग में हैंडपम्पों को ठीक करने के निर्देश दिए।

जीएमवीएन को समय से टैंट का कार्य पूरा करने, संचार को बेहतर करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्ग एवं केदारनाथ धाम में खाद्य पदार्थों की रेट सूची अनिवार्य रूप से लगाने, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल, लकड़ी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सहायक परिवहन अधिकारी को शटल व्यवस्था के लिए जरूरी कार्मिकों की तैनाती करने को भी कहा।

यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक को प्लान तैयार करने को कहा गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे, डीएफओ केदारनाथ इंद्र सिंह नेगी, सीडीओ नरेश कुमार, एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी, सीईओ बीकेटीसी योगेंद्र सिंह, एसडीएम ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा, एसडीएम सदर अपर्णा ढौंडियाल, जखोली परमानंद राम, डीडीओ मनविंदर कौर, सीओ प्रबोध कुमार घिल्डियाल, सीओ यातायात हर्षवर्धनी सुमन, सीएमओ डॉ एचसी मार्तोलिया, सीवीओ डॉ आशीष रावत, ईई डीडीएमए प्रवीण कर्णवाल, पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान संजय सिंह, जल निगम नवल कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार आदि अफसर मौजूद थे।

असामाजिक तत्वों ने युवाओ के आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ा : बंशीधर भगत

देहरादून। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाढुंगी के भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व बेरोजगारों के आंदोलन को दिशाहीन करने की कोशिश में लगे हैं। शुक्रवार को भगत ने कहा कि बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ राजनीतिक रोटियां सेंकने की मंशा रखने वाले असामाजिक तत्वों ने युवाओ की भीड़ में उनके आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला युवा कभी कानून को अपने हाथ में नही लेता, क्योंकि वह संविधान में दिए अधिकारों से अपनी बात रखना जानता है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य का युवा निःसंदेह प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट होने जैसी घटनाओं से आहत हैं।। बावजूद इसके वह पथराव व आगजनी कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बेरोजगार युवाओं के प्रति चिंता का ही नतीजा है कि धामी सरकार ने युवाओं की मेहनत पर पानी फेरने का अपराध करने वाला हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आरोपी सख्स सलाखों के पीछे है। भगत ने कहा राज्य सरकार के सख्त नकलरोधी कानून में नकल माफिया को उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया।

आयुष प्रदेश बनाने को एकजुट होकर किए जाएं प्रयास

देहरादून। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के चौथे बोर्ड के नए नामित और निर्वाचित सदस्यों ने उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने को एकजुट होकर प्रयास किए जाने पर जोर दिया। पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास को प्रयास किए जाएं। बैठक में परिषद अध्यक्ष डॉ जेएन नौटियाल, रजिस्ट्रार नर्वदा गुसांई, दिनेश जोशी, सुनील कुमार रतूड़ी, धीरज आर्य, पंकज कुमार, सुनील कुमार आर्य, वीरेन्द्र सिंह, श्रीकान्त सिंह, बालकृष्ण पंवार, विशाल वर्मा, धीरज त्यागी, शादाब खान मौजूद रहे।

संपादकीय

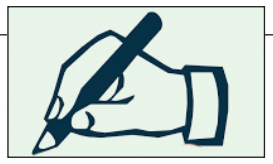

महंगाई अभी भी चिंता की वजह

महंगाई में आंशिक कमी के बावजूद मौद्रिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है. उपभोक्ता मूल्य पर आधारित महंगाई दर दिसंबर में घटकर 5.72 प्रतिशत रह गयी, जो नवंबर में 5.88 प्रतिशत थी. अक्तूबर में यह 6.77 प्रतिशत और सितंबर में 7.41 प्रतिशत रही थी. अभी यह रिजर्व बैंक द्वारा तय महंगाई दर की ऊपरी सीमा छह प्रतिशत से नीचे है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई भी दिसंबर में घटकर 4.95 प्रतिशत पर आ गयी. उल्लेखनीय है कि मई में यह 15.88 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी थी. रिजर्व बैंक अमूमन अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की नीतियों का अनुसरण करता है. अमेरिका में नवंबर में महंगाई दर 7.1 प्रतिशत रही, जबकि मई में यह 8.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गयी थी. चूंकि अमेरिका में महंगाई की ऊपरी सहनशीलता सीमा दो प्रतिशत है, इसलिए वहां महंगाई को बेकाबू माना जा रहा है. इसी कारण फेडरल रिजर्व ने हाल में फिर से नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की है, जिससे नीतिगत दर 4.50 से बढ़कर 4.75 प्रतिशत हो गयी है. फेडरल रिजर्व बैंक ने अब तक नीतिगत दरों में 450 आधार अंकों की वृद्धि की है. बैंक ऑफ कनाडा ने भी विगत दिनों नीतिगत दर में वृद्धि की है, जिससे यह 4.5 प्रतिशत हो गयी है. यह बैंक इस दर में 12 महीने से कम समय में आठ बार वृद्धि कर चुका है. ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में वहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 11.1 प्रतिशत हो गयी, जो 1981 के बाद सबसे अधिक है. हाल में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, जिससे यह चार प्रतिशत हो गयी है. यह 2008 के बाद सर्वाधिक है. उल्लेखनीय है कि यह बैंक महंगाई पर काबू करने के लिए बीते महीनों में नीतिगत दर में 10 बार इजाफा कर चुका है. भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2022 से रेपो दर बढ़ाना शुरू किया था. उस वक्त यह चार प्रतिशत थी. तीन मई को रेपो दर में 0.40 प्रतिशत, आठ जून को 0.50 प्रतिशत, अगस्त में 0.50 प्रतिशत, सितंबर में 0.50 प्रतिशत, दिसंबर में 0.35 प्रतिशत और अब आठ फरवरी, 2023 को 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी, जिससे यह 6.50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गयी है.

दैनिक न्यूज़ वायरस
संपादक : मौ.सलीम सैफी, कार्यकारी संपादक : आशीष कुमार तिवारी न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मौ.सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से प्रकाशित एवं न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून से मुद्रित। **फ़ोन :** 0135-4066790, 2672002 **RNI No. :** UT-THIN/2012/44094 **Cert. Ser. No. :** 31406 **E-mail :** dainiknewsvirus@gmail.com **Website :** www.newsvirusnetwork.com **YouTube :** TV News Virus
न्याय क्षेत्राधिकार : जनपद देहरादून (उत्तराखंड), भारत

संक्षप्ति खबरें

संदिग्ध कार से 13 पेटी शराब बरामद

ऋषिकेश। शहर में एक संदिग्ध कार से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 13 पेटियां बरामद की है। तस्कर पुलिस हत्थे नहीं चढ़ सका है। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। कार को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रेलवे रोड पर एक संदिग्ध कार दिखी। कार की तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब के अलग-अलग ब्रांड की 13 पेटियां बरामद हुई। मौके पर कोई शख्स पुलिस को नहीं मिला, जिसके चलते पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आबकारी ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक खुशी राम पांडे ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर अज्ञात की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शिनाख्त होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

गन्ना किसानों का खरीद इंडेंट बढ़ाए चीनी मिल प्रशासन

ऋषिकेश। गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने डोईवाला चीनी मिल के ईडी से मुलाकात की। उन्होंने गन्ना किसानों का गन्ना खरीद इंडेंट बढ़ाने और डोईवाला में बीज शोध केंद्र को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। शुक्रवार को कांग्रेस नेता गौरव सिंह के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल डोईवाला चीनी मिल पहुंचा। वहां उन्होंने अधिशासी निदेशक डीपी सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं को रखा। उन्होंने डोईवाला क्षेत्र के गन्ना किसानों की खरीद का इंडेंट बढ़ाने की मांग की। उन्होंने डोईवाला क्षेत्र में बीज शोध केंद्र को सुचारू रूप से चलाने की भी मांग की। अधिशासी निदेशक डीपी सिंह ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही गन्ना किसानों का गन्ना खरीद इंडेंट बढ़ाएंगे। मौके पर किसान नेता जसवंत सिंह, नागेंद्र सिंह, सोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजन, अजय रावत आदि उपस्थित रहे।

संदिग्ध हालात में गंगा में कूदा युवक

ऋषिकेश। साईंघाट पर संदिग्ध हालात में एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से युवक की तलाश को सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर उसका कोई सुराग नहीं लग सका। त्रिवेणीघाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार के मुताबिक शुक्रवार को साईंघाट पर यह घटना शाम करीब सवा पांच बजे की है। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। एसडीआरएफ की मदद से युवक की गंगा में तलाश की गई, बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगा है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में युवक कुछ देर के लिए घाट पर बैठा भी दिखा है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। इस बाबत आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस को सूचित किया गया है। स्थानीय स्तर पर भी युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

अतिक्रमण हटाने को दिया दो दिन का अल्टीमेटम

ऋषिकेश। नेशनल हाईवे चौड़ीकरण को लेकर एनएच पीडब्ल्यूडी डोईवाला अब एक्शन में आई है। नगर क्षेत्र में मुनादी के जरिए अतिक्रमणकारियों को 12 फरवरी तक खुद ही कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। बावजूद, हाईवे की घेरबाड़ नहीं हटाने पर विभाग की टीम जेसीबी से अतिक्रमण हटाएगी। शुक्रवार को एनएच पीडब्ल्यूडी का मुनादी वाहन दिनभर शहर में घूमता रहा। इस दौरान नेशनल हाईवे पर चिन्हित 53 अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने की चेतावनी जारी की गई। अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि नोटिस के जरिए पहले ही अतिक्रमण को लेकर संबंधित लोगों को आगाह किया गया है। किसी के पास वैध दस्तावेज हैं, तो 13 फरवरी को विभागीय कार्यालय डोईवाला में उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्धारित समयसीमा में स्वयं कब्जा नहीं हटाने पर डिविजन की टीम 14 फरवरी को जेसीबी से राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। बताते चलें कि, साल 2021 से करीब 14 करोड़ रुपये शहर में नेशनल हाईवे के कोयलघाटी से चंद्रभागा पुल तक दो किलोमीटर पैच के चौड़ीकरण के लिए स्वीकृत हैं। विभाग निर्माण कार्य के लिए निजी एजेंसी भी हायर कर चुका है, जोकि मौके पर काम भी कर रही है, लेकिन अतिक्रमण के चलते चौड़ीकरण कार्य प्रभावित हो रहा है।

राजनीति में कोई भी स्थाई दुश्मन नहीं होता: भट्ट

ऋषिकेश। भाजपा ऋषिकेश जिला कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने और भाजपा की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। शुक्रवार को जौलीग्रांट स्थित शिव शक्ति फार्म में भाजपा ऋषिकेश जिला कार्यसमिति की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता स्वयं को कम न समझें, बल्कि स्वयं के अंदर नेतृत्व क्षमता को जागृत करे। उन्होंने भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि स्वयं को बुद्ध जैसा बनाएं। जिस प्रकार बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर सभी लोग उनके समर्थक हो गए थे, उसी प्रकार स्वयं के विचारों से लोगों को प्रभावित करें। कहा कि राजनीति में कोई भी स्थाई दुश्मन नहीं होता है। कब कौन आपके साथ खड़ा मिले, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तीर्थ स्थानों को महत्त्व दिया जा रहा है। आज राम मंदिर को बनते हुए हम देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1036 करोड़ रुपये की लागत से डोईवाला से ऋषिकेश फोरलेन को एलिवेटेड रोड बनाने की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसानों के लिए 75 हज़ार करोड़ रुपये दिये जा रहे है। साथ ही सप्त ऋषि योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है। बजट में हमारे उत्तराखंड के अनाज मंडवे का जिक्र होना ही बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, ऋषिकेश मेयर अनिता ममगाईं, विधायक बृजभूषण गैरोला, जिला महामंत्री राजेन्द्र तडियाल, दीपक धमीजा, मनोज ध्यानी, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, रविंद्र बेलवाल, प्रतीक कालिया, गणेश रावत, सरोज दिमरी, मनोज ध्यानी, नीलम काला चमोली, कविता शाह, पुष्पा ध्यानी, राजेश जुगलान, पंकज शर्मा, राहुल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

बेरोजगारों पर लाठीचार्ज निंदनीय: महेंद्र भट्ट

ऋषिकेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीते गुरुवार को प्रदेश में बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। सरकार पूरी तरह युवाओं के साथ है। शुक्रवार को डोईवाला के जौलीग्रांट में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के लिए कार्य कर रही है। इसी को लेकर धामी सरकार ने उत्तराखंड प्रदेश में नकल विरोधी कानून बनाया है। जिसमें नकल करने व कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिससे प्रदेश में होनहार युवाओं को सरकारी सेवाओं में जाने का सीधा फायदा मिलेगा। सरकार नई भर्तियां भी निकालने जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं उन्होंने बेरोजगार युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा संयम के साथ अपनी मांग रख सकते हैं और सरकार भर्ती घोटालों को लेकर लगातार नाम उजागर कर रही है।

प्रथम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में जमकर बरसे पुरुस्कार

‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना ने बदल दी स्टेट जीएसटी की तक़दीर

वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल और जीएसटी कमिश्नर डॉ अहमद इक़बाल ने बढ़ाया आम लोगों का हौसला

- आम नागरिक जमकर कर दे रहे है सहयोग,लगातार बढ़ रहा है जीएसटी कलैक्शन
- योजना ने जीएसटी चोरों की तोड़ दी क़मर
- अब हर कोई नॉन ब्रांडेड वाले दुकानदारों से मांग रहा है जीएसटी बिल
- योजना के चलते उपभोक्ताओं द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया

मो.सलीम सैफी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। 10 फ़रवरी । उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अब तक दो मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किये गये हैं। इस क्रम में विजेताओं को पुरस्कार दिये जाने हेतु राज्य कर मुख्यालय परिसर में वित्त मंत्री डॉ0 प्रेम चन्द अग्रवाल की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में वित्त मंत्री द्वारा विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार जैसे स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच तथा इयर पोड वितरित किये गये।

राज्य कर मुख्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह सहित सम्भागीय कार्यालयों में भी “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के अन्तर्गत विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये, जिसके अंतर्गत राज्य में विभिन्न स्थानों यथा हरिद्वार, रुद्रपुर तथा हल्द्वानी में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोहों में विभिन्न पुरस्कार वितरित किये गये। इस अवसर पर वित्त मंत्री द्वारा यह अवगत कराया गया कि योजना के अन्तर्गत अब तक 18,655 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 28,893 बिल अपलोड किये गये हैं तथा यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि योजना का प्रथम लकी ड्रॉ दिनांक 12 दिसम्बर, 2022, दूसरा लकी ड्रॉ दिनांक 16 जनवरी, 2023 को निकाला गया था तथा तीसरा लकी ड्रॉ दिनांक 13 फरवरी, 2023 को प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने बताया कि योजना के प्रति जनता में अत्यधिक उत्साह का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है। पंजीकृत उपभोक्ताओं में सर्वाधिक बिल अपलोड करने वालों में हरी राम टम्टा 91 बिल, साहिल शाह 83 बिल, हर्षित पाण्डे 82 बिल, राजन सिंह 77 बिल शामिल हैं। इसी प्रकार विक्रेता व्यापारियों में से सर्वश्री रिलायंस रिटेल लि0 के 1664 बिल, सर्वश्री अशोक अनिल इन्टरप्राइसेस के 1166 बिल, सर्वश्री एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग प्रा0लि0 के 916 बिल अपलोड किये गये हैं। भविष्य में ये योजना सेवा प्रदाता और दुकानदारों के लिए भी शुरू किए जाने के संकेत वित्त मंत्री ने दिए वित्त मंत्री द्वारा प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह की वृद्धि में “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना की भूमिका से अवगत कराते हुए समस्त जनता से खरीद पर बिल प्राप्त करते हुए राज्य के विकास तथा खुशहाली में योगदान देने की अपील की गयी। यह अवगत कराया गया कि गत वर्ष 2021-22 (माह जनवरी तक) रु0 4625 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2022-23 (माह जनवरी तक) में रु0 6236 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 35% अधिक है 1 माह जनवरी, 2022 में प्राप्त राजस्व रु0 526 करोड़ की तुलना में माह जनवरी, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 640 करोड़ है, जो कि लगभग 22% अधिक है।

योजना 31 मार्च तक जारी

विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी सहायता तथा जानकारी हेतु विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निराकरण के प्रयोजन से संपर्क किया जा सकता है। जीएसटी कमिश्नर डॉ अहमद इक़बाल ने अपने ज़ोरदार संबोधन में इस योजना की बारीकियों को शेयर किया।

आम जनता को सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जीएसटी कमिश्नर डॉ अहमद इकबाल ने आह्वान किया कि इस योजना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा ले क्योंकि जीएसटी की ये योजना राज्यहित के साथ साथ पारदर्शी टैक्स व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही हैपुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं सहित डॉ0 अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आई0एस0बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, डॉ0 सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, एस0एस0तिरुवा और सुश्री प्रीति मनराल उपायुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।